Infiltration and smuggling at Kutch border in Gujarat

श्री अनन्तराय देवशंकर रावल (गुजरात): मैं अपने स्पेशल मेंशन के द्वारा सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हम जानते हैं कि अभी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पिछले दो साल से सूखा पड़ा हुआ है । वेस्टर्न पार्ट आफ दी कच्छ पूरा खाली हो गया है । वहां पर हमारी जो सरहद है जो बिलकुल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, हमारे गृह राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वहां आज भी स्मगलिंग चलती रहती है । पिछले दिनों में 18 तारीख को तीन करोड़ का सोना पकड़ा गया । मेरे पास डाकुमेंट हैं कि वर्ष 1991 में एक भी महीना ऐसा नहीं रहा जब लाखों करोड़ों की चांदी या सोना न पकड़ा गया हो । लेकिन सितम्बर मास के बाद से जब से सरहद सील कर दी गई है, उसी समय से हर महीने दो आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 18 आदमी, 21 आदमी उस सरहद से पाकिस्तान से घुस कर हमारी सरहद में आते हुए पकड़े गए । पहले स्मगलिंग चलती थी, लेकिन अब सिलसिला चेंज हो गया है । यह जो आदमी पकड़े गए हैं वह हथियारों के साथ पकड़े गए हैं । आज से पहले भी मैंने कई बार इस सवाल को सदन में उठाया है और यह कहा है कि वहां पर कुछ कांसपिरेसी चल रही है, कोई जासूसी प्रवृत्ति भी चल रही है । एयर फोर्स का भी एक आदमी जुलाई में पकड़ा गया था । लेकिन आज दिन तक उस सरहद को सील करने के बावजूद भी वहां से आदमी आ रहे हैं । बहुत मात्रा में दिन प्रति दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है । इसी वजह से मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि यदि इस सड़क पर ज्यादा नजर नहीं रखी जाएगी या ज्यादा फोर्स नहीं रखी जाएगी तो हर रोज—क्योंकि सूखे की वजह से वहां कोई लोग नहीं रह रहे हैं, पूरा वेस्टर्न पार्ट खाली हो गया है, वहां कोई आदमी नहीं है और जो आदमी हैं वे काम करने थोड़ी दूर चले गये हैं इसलिए यह जगह नो मैंन्स लैंड हो गयी है और वहां से पाकिस्तान से लोग आते रहेंगे ।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं । हमारी सरहद के जो पिलर लगे हुए हैं वहां 1175 नं० के पिलर के बाद कोई पिलर नहीं है वह जमीन पाकिस्तान की अपनी है इस तरह का विवाद उसने खड़ा कर दिया है । जो एक और क्रीक है वहां पर जहां ओ.एन.जी.सी. ने बोर किया हुआ है वहां तेल, क्रूड आयल और नेचूरल गैस निकली है लेकिन विवाद में वह जमीन फंस गयी है । इसीलिए मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस जगह पर ज्यादा फोर्स लगायें, ज्यादा नजर रखें ताकि कोई आदमी वहां से नहीं आए, कोई वीपन्स न आयें.... (समय की घंटी) मैं एक मिनट और बात करके अपनी बात फिनिश कर रहा हूं । सूखे की वजह से एक आदमी वहां भूख से मर गया है । गुजरात सरकार ने इन्क्वायरी बैठायी है । वह दो महीने से काम पर गया लेकिन के वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको पेमेंट नहीं किया इसलिए वह आदमी भूख की वजह से मर गया । यह भी एक शर्मनाक घटना है । मैं यहां से अपील करना चाहता हूं कि जिन मजदूरों ने काम किया और उनको दो महीने तक जिन अफसरों ने पेमेंट नहीं किया उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लेना चाहिए । यही मेरा गवर्नमेंट से नम्र निवेदन है । धन्यवाद ।

उपसभापति (श्रीमती सरला माहेश्वरी): आप जल्दी से बोल दीजिए ।

Need to release immediate financial assistance for Teesta Barrage Project

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मैं डेढ़ मिनट भी नहीं लूंगी ।

महोदया, मैं अपने विशेष उल्लेख के जरिये आज सदन का ध्यान पश्चिमी बंगाल की जनता के लम्बे अर्से से उपेक्षित मांग की ओर दिलाना चाहती हूं । यह वहां की जनता की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ प्रश्न है । पूरे उत्तरी बंगाल में

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

कृषि के विकास की सभी संभावनायें इससे जुड़ी हुई हैं । यह मांग तिस्ता सिंचाई प्रकल्प से सम्बद्ध है ।

इस महत्वपूर्ण प्रकल्प की योजना आजादी से पहले, 1945 में ही बन चुकी थी । लेकिन इसे अनुमोदन मिला 28 वर्ष बाद 1973 में । उस वक्त इस पर 6 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत रखी गयी थी । योजना आयोग ने भी इसे 1975 में अनुमोदित कर दिया लेकिन उसके बाद भी अनेक बाधाओं तथा केन्द्रीय उदासीनता के कारण उस पर कोई अमल नहीं किया जा सका । 1987 में फिर जब प्रकल्प पर अनुमोदित लागत का हिसाब कूता गया तो वह 510 करोड़ रुपये पाया गया । 14 वर्ष में खर्च लगभग 8 गुना बढ़ गया । आज तो वह खर्च और भी अधिक हो गया है ।

1977 में ही सत्ता में आने के ठीक बाद पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने इस प्रकल्प पर काम शुरू करने और इसके लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता की मांग उठायी थी लेकिन केन्द्रीय सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । इसके बाद अपनी पहल पर ही वामपंथी सरकार ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है । आज की परिस्थितियों में राज्य सरकार की आर्थिक शक्ति कितनी है, इसका तो सबको अनुमान है । फिर भी, तमाम बाधाओं और मुसीबतों का सामना करते हुए भी वाम-मोर्चा सरकार ने इस प्रकल्प पर अब तक लगभग 320 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं । केन्द्रीय सरकार ने अब तक सिर्फ 5 करोड़ रुपये दिये हैं ।

तिस्ता प्रकल्प के प्रति केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा से राज्य की जनता में गहरा आक्रोश है । यह राज्य के प्रति सरासर अन्याय है । केन्द्रीय सरकार की उदासीनता के चलते पूरे उत्तर बंगाल में विकास का कार्य रुका हुआ है । आजादी के बाद से अब तक भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, शतद्रु-यमुना परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तरह की कितनी ही सिंचाई परियोजनाओं पर अमल हुआ है लेकिन पश्चिम बंगाल में इस अकेले महत्वपूर्ण प्रकल्प के प्रति ऐसी उदासीनता क्यों बरती जा रही है । इस सदन के जरिये मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि वह तत्काल इस परियोजना पर कुछ लागत के 50 प्रतिशत हिस्से को राज्य-की वाम मोर्चा सरकार को योजना अनुदान के रूप में अनुमोदित करे । इस प्रकल्प से उत्तरी बंगाल की विशाल एक फसली, दो फसली जमीन को तीन फसली जमीन का रूप दिया जा सकेगा । हमें आशा है कि राष्ट्र के हित में ही केन्द्रीय सरकार इस मामले में अब और विलम्ब नहीं करेगी वरना आश्चर्य नहीं कि इस प्रश्न पर पूरे पश्चिम बंगाल की जनता केन्द्रीय सरकार के अन्यायपूर्ण उदासीनता के खिलाफ खुले संघर्ष के रास्ते पर उतर पड़े । धन्यवाद ।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal) : Madam, I join her in the demand and request the Government to fulfil these demands on which depends the prosperity not only of North Bengal but of Eastern India also.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Prof. Chandresh P. Thakur)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHENDESH P. THAKUR) : Well, we have two Special Mentions still left. One is by Mr. Aurora.